

स्वच्छ भारत अभियान में तेजी

*नीरज बाजपेयी

वर्षभर से चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम 'स्वच्छ भारत अभियान' (एसबीएम) में नई ऊंचाइयां हासिल करने के राष्ट्र के प्रयासों का यह प्रतिफल है कि देशभर में सफाई और स्वच्छता के प्रति सामान्य जागरूकता "एक संक्रामक मुस्कान" की तरह फैलती जा रही है। सफलता की कहानियों का अम्बार और स्वच्छता के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता से संकेत मिलता है कि यह सिर्फ एक कागज़ी बाघ परियोजना नहीं है।

अभियान और उससे संबंधित कार्यों को अंजाम देने के लिए, न केवल अधिकारी बल्कि अभियान में शामिल अनेक सामाजिक संस्थाएं और निकाय आंकड़ों का ढेर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर चुके इस विशाल कार्य में आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है। स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के काम में अब ज्यादा से ज्यादा सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं शामिल हो चुकी हैं। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि एसबीएम सरकार के प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है, परंतु, अनेक दूसरे उपाय जहां अधिकतर मांग संचालित होते हैं, वहीं, इस कार्यक्रम का लक्ष्य सफाई सेवाओं और ढांचे की मांग खड़ी करना है और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वे सफाई के प्रति सही व्यवहार करें।

श्री नायडू ने एसबीएम को उसके विशिष्ट स्वरूप को देखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सभी नए कार्यक्रमों की जड़ बताया। श्री नायडू ने कहा कि एक स्वच्छ भारत सर्वाधिक सशक्त वायदा है जो भारत विश्व के उन देशों से कर सकता है, जो पिछले एक वर्ष के दौरान शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में भारत की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री द्वारा अभियान का शुभारंभ किए जाने के बाद से देश के सभी भागों और सभी आयु समूहों के लोग कार्यक्रम की विचारधारा और लक्ष्यों से प्रेरित हुए हैं, और यही इसकी प्रमुख उपलब्धि है।

व्यवहार विषयक परिवर्तनों को अधिक सुदृढ़ और समेकित बनाने के लिए पिछले महीने एक गहन अभियान प्रारंभ किया गया और यह अगले वर्ष मार्च तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत लोगों को सफाई कार्यों में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया जाएगा और 11 विषयपरक क्षेत्रों में गहन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इन क्षेत्रों में कृषि और अनाज मंडियां, धार्मिक और पर्यटन स्थल, शैक्षिक संस्थान, निवासी कल्याण संगठन, अंडर पासों और फ्लाइओवरों, छावनी बोर्डों, जल निकायों, मनोरंजन स्थलों, अस्पतालों, पुराने शहरी क्षेत्र और सरकारी कार्यालयों को शामिल किया जाएगा।

एक स्वच्छ भारत सभा स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है। इस वर्ष अगस्त तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ने पृथक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के संदर्भ में बेहतर कार्य निष्पादन किया है। मार्च, 2016 तक शहरी क्षेत्रों में 25 लाख घरेलू शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 16.45 लाख शौचालयों का निर्माण शुरू किया गया, जिनमें से 4.65 लाख शौचालय पहले ही निर्मित हो चुके हैं। एसबीएम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री नायडू ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु सहित बड़े राज्यों को अभी इस काम में तेजी लानी है। उनके अनुसार 5 संघ शासित प्रदेशों-अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और दिल्ली तथा 4 पूर्वोत्तर राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा तथा केरल और तमिलनाडु में अभी शौचालय निर्माण का काम प्रारंभ होना है।

कई राज्यों के उत्साह की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि शहरी राज्यों में प्रत्येक शौचालय के निर्माण के लिए 4000 रुपये प्रति शौचालय की केंद्रीय सहायता से बढ़ कर, 13 राज्य 4000 रुपये से 13000 रुपये के बीच अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के बारे में उन्होंने बताया कि सरकारी रिकार्डों के अनुसार मार्च, 2016 तक 1,00,000 शौचालयों का निर्माण करने के लक्ष्य की दिशा में, 94,653 शौचालय सीटों का निर्माण शुरू किया गया, जिसमें से 24,233 सीटें पहले ही बन कर तैयार हो चुकी हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है।

मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन इस अभियान का सबसे बड़ा घटक है। देश के कुल 78,003 वार्डों में से 31,593 वार्डों में घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने की शत-प्रतिशत व्यवस्था कायम की जा चुकी है। अभियान के अंतर्गत मार्च, 2016 तक घर-घर जाकर ठोस कचरा एकत्र करने की 50 प्रतिशत व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में हर रोज उत्सर्जित 1,42,580 टन ठोस कचरे में से 35 प्रतिशत को प्रोसेस करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अभी तक 17.34 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

कुछ शहरी स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन के बारे में श्री नायडू ने कहा कि गुजरात में सूरत और मोरबी क्रमशः 6,634 और 3,028 पारिवारिक शौचालय इकाइयों के निर्माण के साथ अभियान का लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं। गुजरात में ही अहमदाबाद और महिसागर भी क्रमशः 22,562 और 3,029 शौचालयों के निर्माण का अभियान का लक्ष्य हासिल करने के अत्यंत निकट हैं। ठोस कचरा प्रबंधन के संदर्भ में बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, जहां कचरे की शत प्रतिशत प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद मेघालय (58 प्रतिशत), दिल्ली (52 प्रतिशत), केरल और मणिपुर (50 प्रतिशत), तेलंगाना (48 प्रतिशत), कर्नाटक (34 प्रतिशत) और अंडमान निकोबार द्वीप समूह (30 प्रतिशत), अहमदाबाद (64 वार्ड), सूरत (38 वार्ड), महिसागर (27 वार्ड) और मोरबी (14 वार्ड) गुजरात और

अंडमान निकोबार द्वीप समूह (प्रत्येक में 30 वार्ड) में ठोस कचरा घर घर जाकर एकत्र करने की शत प्रतिशत व्यवस्था किए जाने की खबर है।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में कुल 66,009 करोड़ रुपये की लागत से घर घर जाकर ठोस कचरा एकत्र करने और उसके वैज्ञानिक निपटान की शत प्रतिशत व्यवस्था के अलावा 1.04 करोड़ पारिवारिक शौचालयों और 5.28 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था। शहरी विकास मंत्रालय अभी तक 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 1,038.72 करोड़ रुपये जारी कर चुका है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के अतिरिक्त संघ शासित प्रदेशों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली एवं लक्षद्वीप को अभी धन जारी किया जाना है।

इन गतिविधियों के बीच सुदूरतम क्षेत्रों तक स्वच्छता अभियान चलाए जाने पर निगाह रखी जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, स्वयंसेवकों तक सभी ध्यान आकृष्ट करते हैं, जब वे प्रतीकात्मक सफाई या झाड़ू लगा रहे होते हैं। इससे कार्यक्रम की गति निर्धारित होती है, लेकिन कई आलोचक भी हैं जो इसे एक ड्रामा मात्र बताते हैं।

केन्द्र सरकार के अनेक मंत्रालयों ने स्वयं के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और रेल यात्रियों की बढ़ती आकांक्षाओं के बीच इस अभियान में रेलवे मंत्रालय की उपलब्धियों और प्रयासों पर विशेष ध्यान केन्द्रित हुआ है। यह अभियान लगभग हर रोज चर्चा का केन्द्रबिन्दु बना रहता है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक दुखी वरिष्ठ नौकरशाह ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि गहन आन्त्र पीड़ा से ग्रस्त उसके एक निकट संबंधी की मौत हो गई, क्योंकि गंदगी से उत्पन्न मच्छरों के कारण राजधानी में फैले घातक डेंगी और अन्य वायरल बुखारों के कारण प्रमुख अस्पतालों में रोगियों की अधिकता को देखते हुए उसे किसी वार्ड में दाखिला नहीं मिल पाया था।

इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि सफाई एवं स्वच्छता अभियानों और व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए हर वर्ष नियमित रूप से होने वाली ऐसी भयंकर बीमारियों को कैसे कारगर ढंग से रोका जा सकता है। कालोनियों में स्वच्छता अभियानों और उनमें लोगों की भागीदारी पर टिप्पणी करते हुए एक अर्धे उम्र के वर्ग 'घ' कर्मचारी के अनुसार "कल्पना कीजिए यदि स्वच्छ भारत जैसा अभियान शुरू नहीं किया जाता, तो ऐसी भयानक बीमारियों का मानव जीवन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता और देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर कितना दबाव बढ़ता। ऐसे अभियानों की सफलताओं और विफलताओं के बारे में सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन पिछले एक वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हर रोज बहस हुई है।" कर्मचारी ने कहा कि राजनीति से हट कर देखें, तो चीजें बदली हैं, "आप इससे सहमत हों

या न हों, स्वच्छ भारत चलन में है और हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी होना अवश्यम्भावी है।” राष्ट्रीय स्वास्थ्य के स्वरूप के बारे में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ऐसी बीमारियों का प्रसार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका दुष्प्रभाव तथा अर्थव्यवस्था पर उसका दबाव रोकने के लिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। अतीत में 4 वर्षों, 2010-14 के दौरान अकेले डेंगी से 820 लोगों की जानें गईं, जबकि बीमारी और मृत्यु के अद्यतन आंकड़ों का संकलन अभी किया जाना है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी बीमारियों का समाधान स्वच्छ वातावरण में निहित है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में स्वच्छ भारत अभियान को समझने की आवश्यकता है। अनेक स्थानों पर निवासी कल्याण समितियां (आरडब्ल्यूए) स्वच्छता अभियान में योगदान करती नजर आईं। वे स्वयं के योगदान से फोगिंग मशीनें खरीदती देखी गईं। निजी क्षेत्र के एक वरिष्ठ कर्मचारी, केरल के श्रीधरन के अनुसार उनके राज्य में स्वच्छता अभियान जोर पकड़ रहा है और अब नगर पालिकाएं अपघटीय कचरे के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ट्यूब वितरित कर रही हैं, जिनमें रखा गया कचरा निर्धारित अवधि के भीतर खाद में परिवर्तित हो जाता है।

वर्ष के दौरान ऐसी कल्याणकारी संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जो प्लास्टिक जैसे गैर-अपघटीय कचरे को एकत्र करती हैं और “री-साइकलिंग के बाद ऐसी रद्दी” के लिए विक्रेता को धन लौटाती हैं। श्री श्रीधरन का सुझाव है कि ऐसे उदाहरणों का देश के अन्य भागों में भी अनुकरण किया जाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2019 तक देश को गंदगी और खुले में शौच जाने से मुक्ति दिलाना है। इसके लक्ष्यों में कार्रवाइयों का एक जटिल समूह शामिल किया गया है ताकि सामाजिक परिवर्तन के मूलभूत उपकरणों के जरिए स्वच्छता की खराब स्थिति और ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में जन-जागरूकता के जरिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष गांधी जयंती पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और इस वर्ष 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, लालकिले के प्राचीर से गर्व पूर्वक स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों का बखान करते हुए बताया कि इसके अंतर्गत बनाए गए शौचालयों और उनके इस्तेमाल की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों से टीम इंडिया के सदस्यों - चाहे वे प्रसिद्ध व्यक्ति, राजनयिक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, सामुदायिक नेता या धार्मिक नेता अथवा मीडियाकर्मी - सभी ने किसी की आलोचना किए और खामियों को उजागर किए बिना, जनसाधारण को प्रशिक्षित करने का बड़ा दायित्व अपने पर लिया है। उन्होंने कहा कि 5, 10 और 15 वर्ष की आयु समूह के बच्चों और किशोरों से इस अभियान को अधिकतम बल मिला है, जो स्वच्छ भारत अभियान के महान अग्रदूत बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि बच्चे माता-पिता को घरों में गंदगी फैलाने से रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि इधर-उधर कूड़ा-करकट न डालें। यदि किसी पिता को गुटखा खाने की लत है और वह थूकने के लिए कार कर दरवाजा खोलता है, तो बच्चे स्वच्छ भारत का तर्क देकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ऐसा देश, जिसमें बच्चे इतने प्रतिबद्ध हों, अवश्य स्वच्छ बनेगा। कचरे और गंदगी से घृणा अवश्य बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि “2019 में जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे होंगे, तो “स्वच्छ भारत” एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें दे सकेंगे।” महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती।

“यह कार्य अभी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे इसे आगे बढ़ाना है, रोकना नहीं है, संतुष्ट होकर नहीं बैठना है। जब हमने काम शुरू किया, टीम इंडिया ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्धारण किया, हमने महसूस किया कि 2,62,000 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें 4.25 लाख शौचालयों का निर्माण कराने की आवश्यकता है। यह संख्या इतनी विशाल थी कि कोई भी सरकार समय सीमा बढ़ाने पर फिर से विचार कर सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से टीम इंडिया का संकल्प था कि किसी ने समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं की।” श्री मोदी के अनुसार इस वर्ष 15 अगस्त तक टीम इंडिया सभी शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 4.25 लाख शौचालयों के निर्माण का मुद्दा नहीं था, यह एक आत्मविश्वास का माहौल बनाने का मुद्दा था, खासकर ऐसे समय “जब हम नकारात्मकता से इतने घिरे हुए हों, और हमसे यह कहा जा रहा हो, कि कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है, यह संभव नहीं है। लेकिन आज टीम इंडिया ने इसे करके दिखा दिया है।”

ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि 35 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 4.18 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है ताकि लड़के और लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग-अलग शौचालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। अन्य भागों में भी प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को राजपथ पर प्रारंभ किए गए ‘स्वच्छ भारत’ अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिला है। 2019 तक इस अभियान के अंतर्गत 4041 सांविधिक शहरों में सभी क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और खुले में शौच जाने से मुक्ति प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस कार्य की अनुमानित लागत 66,009 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 14,643 करोड़ रुपये की है।

राष्ट्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 14,623 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं, इसके अतिरिक्त 4,874 करोड़ रुपये की न्यूनतम अतिरिक्त राशि (भारत सरकार के योगदान के 25 प्रतिशत के समकक्ष) राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अदा की जाएगी। शेष धन अन्य स्रोतों से जुटाए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों से अपेक्षा है कि वे 2008 की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुसार नगर स्वच्छता योजनाएं और राज्य स्वच्छता कार्यनीतियां तैयार करें।

अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों में मिश्रित कार्रवाइयों का एक समूह शामिल किया गया है, जिन्हें सामाजिक परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन और स्वच्छता की खराब स्थिति एवं ठोस कचरा प्रबंधन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जन-जागरूकता के माध्यम से संचालित किया जाना है।

इस बदलाव को संस्थागत रूप देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान म्युनिसिपल अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का सुझाव देता है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ई-लर्निंग कार्यक्रम म्युनिसिपल कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण और स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक नया प्रयास है। यह नगर प्रबंधकों को लचीलापन प्रदान करता है और उन्हें सीखने के लिए स्वयं का एक विकल्प उपलब्ध कराता है। यह मंच वीडियो के साथ एक ही स्थान पर प्रमुख पद्धतियों, प्रौद्योगिकी विकल्पों और समान शिक्षण प्रणालियों को प्रस्तुत करता है। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार यह सात घटकों में विभाजित है।

इन घटकों में भारत में शहरी स्वच्छता, नगरीय ठोस कचरे का प्रबंधन, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) और जन-जागरूकता, सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) और वित्त व्यवस्था एवं अन्य प्रासंगिक माइयूल्स शामिल हैं। 'स्वच्छ भारत' के लिए अपेक्षित प्रयासों का महत्वाकांक्षी स्तर हासिल करने के लिए इस अभियान में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के जरिए निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें आंध्र प्रदेश में स्वच्छ भारत कॉर्पोरेशन की स्थापना; तेलंगाना में प्रत्येक वार्ड में 'परिचय' की धारणा का शुभारंभ ताकि नागरिकों को श्रम से परिचित कराया जा सके; कर्नाटक में कम्पोस्टिंग सुविधाओं की स्थापना; तमिलनाडु में "नम्मा शौचालयों" की स्थापना; अगली इंडियन ग्रुप द्वारा शहरों में गंदगीयुक्त कोनों को स्वच्छ स्थलों में बदलने के प्रयास; माता अमृतानंदमयी द्वारा अभियान के लिए 100 करोड़ रुपये का योगदान और अनेक केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम शुरू किया जाना आदि शामिल हैं।

{*नीरज वाजपेयी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) में संयुक्त सम्पादक हैं}

(पीआईबी फीचर)